



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2004/माघ 24, 1925

No. 164]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2004/MAGHA 24, 1925

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2004

प्रस्तावना

का. आ. 195(अ).—यतः दिनांक 9-11-2000 से उत्तरांचल के गठन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश वन निगम दिनांक 1-4-2001 तक उत्तरवर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में कार्य करता रहा;

और यतः उत्तरांचल सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अनुसरण में एक विधायन अधिनियमित करके दिनांक 1.4.2001 से उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना की ;

और यतः उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें वर्तमान उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तरांचल वन विकास निगम के बीच पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश वन निगम की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संविभाजन के लिए प्रयास करती रही हैं ;

और यतः इन दोनों सरकारों के बीच कोई सौहार्द्रपूर्ण समाधान न होने के कारण उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश सरकारों ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश वन निगम की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संविभाजन के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए इस मामले को केन्द्र सरकार को भेज दिया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तरांचल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें की ताकि इस संबंध में उनके विचार जाने जा सकें;

और यतः दोनों सरकारों के बीच उन सिद्धांतों पर कोई सहमति नहीं हो सकी जिनके द्वारा इन परिसम्पत्तियों के संविभाजन को शासित किया जाना चाहिए ;

और यतः दोनों राज्यों द्वारा सुझाए गये निम्नलिखित अलग-अलग मानदंडों पर विचार किया गया है और उनकी जांच की गई है :

- (i) आरक्षित वन क्षेत्र का अनुपात
- (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व/बिक्री मूल्य का अनुपात
- (iii) दस वर्ष की अवधि के निवल लाभ का अनुपात
- (iv) पिछले तीन वर्षों में भुगतान की गई रायल्टी का अनुपात
- (v) पिछले तीन वर्षों में टिम्बर के उत्पादन का अनुपात
- (vi) जनसंख्या का अनुपात
- (vii) स्टाफ का अनुपात

और यतः ऊपर उल्लिखित विभिन्न विकल्पों पर निम्न प्रकार विचार किया गया :—

(i) उत्तरांचल द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र के अनुपात के आधार पर संविभाजन करने के मानदंड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि उत्तरांचल पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में केवल मैदानी क्षेत्र हैं और इसके अतिरिक्त, उत्तरांचल में औसत समुद्र तल से ऊपर 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के बीच आरक्षित वन क्षेत्र का अनुपात 58:42 है। यद्यपि आरक्षित वन क्षेत्र अपरिवर्तित रहा है, फिर भी संबंधित राज्यों के बीच आरक्षित वन क्षेत्र के अनुपात का उनके प्रचालन के स्तर के साथ कोई प्रत्यक्ष सहसंबंध नहीं है। अतः इस मानदंड को परिसम्पत्तियों के संविभाजन का आधार मानना उचित नहीं समझा गया है।

(ii) उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के बीच पिछले तीन वर्षों, पांच वर्षों एवं दस वर्षों का बिक्री (टर्न ओवर) का अनुपात 50.44:49.56 से 54.25:49.75 के बीच रहा है। राज्यों ने बिक्री (टर्न ओवर) के अनुपात के आंकड़े थोड़े भिन्न-भिन्न दिए हैं, हालांकि यह अनुपात 50:50 के लगभग रहा है। दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण इस मानदंड को अपनाया व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

(iii) पिछले तीन वर्षों, पांच वर्षों एवं दस वर्षों के लाभों के अनुपात में काफी उतार-चढ़ाव आता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से में आने वाले संचयी लाभों पर ब्याज को शामिल किया है जिस पर उत्तरांचल सरकार सहमत नहीं है। मुख्यालय लखनऊ में होने के कारण उत्तर प्रदेश के हिस्से में आने वाले लाभों पर अर्जित ब्याज को घटाए बिना लाभों के अनुपात में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का संविभाजन करना तर्क संगत नहीं है।

(iv) उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के बीच पिछले तीन वर्षों में भुगतान की गई रायल्टी का अनुपात 53.5:46.5 है जबकि, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार यह 50.67:49.33 है। यह एक नया प्रस्तावित मानदंड है तथा यह विगत में सचिवों की संयुक्त समिति के विचारार्थ एक विकल्प नहीं था। अतः इसे परिसम्पत्तियों के संविभाजन का आधार मानना उचित नहीं समझा गया है।

(v) विगत तीन वर्षों में टिम्बर के उत्पादन के अनुपात पर भी दोनों राज्यों, मुख्यतः उत्तर प्रदेश ने इस आधार पर सहमति नहीं दी कि तेंदुपत्ता काफी मूल्यवान वन उत्पाद है किंतु यह केवल उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्रों में ही पैदा होता है।

(vi) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में परिभाषित किये गये अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य जनसंख्या का अनुपात 1321:70 है। उत्तरांचल सरकार निगम की परिसम्पत्तियों के बंटवारे के इस मानदंड से सहमत नहीं है क्योंकि दोनों राज्यों की जनसंख्या के मध्य के अनुपात का दोनों राज्यों में निगम के प्रचालन तथा कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। उत्तरांचल सरकार के तर्क में औचित्य है। अतः इस मानदंड को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

(vii) दोनों राज्य सरकारों ने पहले ही निगम के श्रेणी III और IV स्टाफ को उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य 'जैसा है जहां है' के आधार पर 55:45 के अनुपात में बांट लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच बांटे गए स्टाफ का अनुपात 46:54 बताया है।

और यतः केन्द्र सरकार स्टाफ के अनुपात को दोनों राज्यों के बीच प्रचालन और कार्यकलापों के स्तर में औचित्यपूर्ण अनुपात मानती है और इसलिए इसे परिसम्पत्तियों और देयताओं के संविभाजन के लिए एक युक्तिसंगत मानदंड समझती है। इस कारण यह उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के वन निगमों के बीच उत्तर प्रदेश वन निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच स्टाफ के अनुपात को 46:54 स्वीकार करना चाहती है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

I. परिभाषाएँ

- (क) 'पूर्ववर्ती निगम' से अभिप्राय है — उस रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम जिस रूप में यह 9 नवम्बर, 2000 से पहले विद्यमान था और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 67 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2001 तक बना रहा;
- (ख) 'उत्तरवर्ती निगमों' का अभिप्राय है—उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम (यू पी एफ सी) तथा उत्तरांचल राज्य के संबंध में उत्तरांचल वन विकास निगम (यू एफ डी सी) ।

II आदेश

(i) परिसम्पत्तियां

- (क) उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल में स्थित पूर्ववर्ती निगम की निर्धारित परिसम्पत्तियां (भूमि और भवन आदि) उस राज्य के उत्तरवर्ती निगम को अन्तरित हो जाएंगी जिस राज्य में वे स्थित हैं ।
- (ख) फील्ड यूनितों की चल परिसम्पत्तियां और भंडार उनकी अवस्थिति के आधार पर अन्तरित हो जाएंगे । मुख्यालय के भंडार, फर्नीचर और वाहन, उनकी खरीद के वर्ष के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के उत्तरवर्ती निगमों के बीच 46:54 के अनुपात में विभाजित हो जाएंगे ।

(ii) देयताएं

- (क) पूर्ववर्ती निगम की परिसम्पत्ति विशिष्ट देयताएं उस उत्तरवर्ती राज्य के उत्तरवर्ती निगम को अन्तरित हो जाएंगी जिसको वह परिसम्पत्ति आबंटित की गयी है ।
- (ख) पूर्ववर्ती निगम की वे देयताएं जो किसी परिसम्पत्ति से सम्बद्ध नहीं हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के दोनों उत्तरवर्ती निगमों के बीच 46:54 के अनुपात में बांट दी जाएंगी ।

(iii) कर्मचारी

पूर्ववर्ती निगम के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के उत्तरवर्ती राज्यों के वन निगमों को दोनों राज्यों के बीच पहले से ही सहमत ढंग से बांट दिया जाएगा ।

(iv) आरक्षित एवं अधिशेष

पूर्ववर्ती निगम के 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र में यथाप्रदर्शित आरक्षित और अधिशेष को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के उत्तरवर्ती निगमों के बीच 46:54 के अनुपात में संविभाजित कर दिया जाएगा ।

[सं. 13012/1/2002-एस आर]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 13th February, 2004

PREAMBLE

S. O. 195(E).—WHEREAS consequent upon the creation of Uttaranchal w.e.f. 9-11-2000 the Uttar Pradesh Forest Corporation continued to function in the Successor States of Uttar Pradesh and Uttaranchal till 1-4-2001;

And whereas the Government of Uttaranchal set up Uttaranchal Forest Development Corporation w.e.f. 1.4.2001 by enacting a legislation in pursuance of section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

And whereas the Governments of Uttaranchal and Uttar Pradesh have been making efforts to apportion the assets and liabilities of erstwhile Uttar Pradesh Forest Corporation between the present Uttar Pradesh Forest Corporation and Uttaranchal Forest Development Corporation;

And whereas having failed to reach an amicable settlement between them, the Governments of Uttaranchal and Uttar Pradesh have referred the matter to the Central Government for issuing directions for apportionment of assets and liabilities of erstwhile Uttar Pradesh Forest Corporation;

And whereas the Central Government convened two rounds of meetings with the representatives of the Government of Uttar Pradesh and the Government of Uttaranchal to ascertain their respective views;

And whereas the two Governments could not arrive at a consensus on the principles that should govern the division of assets;

And whereas the following different criteria suggested by either of the States have been considered and examined: -

- (i) Ratio of reserve forest area
- (ii) Ratio of revenue/sale value during the last three years

- (iii) Ratio of net profit over a period of 10 years
- (iv) Ratio of royalty paid in the last three years
- (v) Ratio of production of timber in the preceding three years
- (vi) Ratio of population
- (vii) Ratio of staff

And whereas the various options discussed above have been considered as follows: -

(i) The criterion of division on the basis of ratio of reserve forest area proposed by Uttaranchal has not been agreed to by the Government of Uttar Pradesh on the ground that Uttaranchal has hilly terrain and Uttar Pradesh has only plain areas and further there is total ban on felling of green trees in areas over 1000 meters above mean sea level in Uttaranchal. The ratio of reserve forest area between Uttaranchal and Uttar Pradesh is 58 : 42. Even though the reserve forest area has remained constant; there is no direct correlation between the ratio of reserve forest area in the respective States with the level of their operation. Therefore, it has been considered inappropriate to adopt this criterion as the basis for division of assets.

(ii) The ratio of sales (turnover) for the preceding three years, five years and ten years has been ranging from 50.44 : 49.56 to 54.25 : 49.75 between Uttaranchal and Uttar Pradesh. The States have given slightly different figures of ratio of sales (turnover), even though the ratio has been around 50:50. In view of absence of consensus between the two States, it has not been considered feasible to adopt this criterion.

(iii) The ratio of profits for the preceding three years, five years and ten years have been fluctuating substantially. The Government of Uttar Pradesh has included interest on accumulated profits in its share, which has not been agreed to by Uttaranchal Government. It is quite unreasonable to apportion the assets and liabilities in the ratio of profits without subtracting the interest earned on profits, which are being put against Uttar Pradesh since the headquarters is in Lucknow.

(iv) The ratio of royalty paid for the last three years between Uttaranchal and Uttar Pradesh is 53.5 : 46.5 while according to the figures furnished by Uttar Pradesh it is 50.67 : 49.33. This is a new criterion proposed and was not an option for consideration before the Joint Committee of Secretaries earlier. It has, therefore, been considered inappropriate to adopt this as a basis for division of assets.

(v) The ratio of production of timber for the preceding three years has also not been agreed to by the two States, primarily, by the Government of Uttar Pradesh on the ground that Tendu Patta is a highly valued forest produce, but it is produced only in Bundelkhand and Vindhya regions of the Successor State of Uttar Pradesh.

(vi) The population ratio in relation to the successor States of Uttar Pradesh and Uttaranchal as defined in the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 is 1321 : 70. The Government of Uttaranchal has disagreed with this criterion for division of assets of the Corporation since there is no correlation between the ratio of population of the two States with the level of operation and activities of the Corporation in the two States. There is merit in the contention of Uttaranchal Government. Therefore, it has not been considered feasible to adopt this criterion.

(vii) The two State Governments had already divided the Class III and IV staff of the Corporation in the ratio of 55:45 between Uttaranchal and Uttar Pradesh on as-is-where-is basis. The Government of Uttar Pradesh has reported the ratio of staff divided between Uttar Pradesh and Uttaranchal as 46 : 54.

And whereas the Central Government considers the ratio of staff as a fair indication of the ratio in the level of operation and activities between the two States and, therefore, a reasonable criteria for division of assets and liabilities, it is inclined to adopt the ratio of staff of 46:54 between Uttar Pradesh and Uttaranchal for the purpose of division of assets of the Uttar Pradesh Forest Corporation between the Forest Corporations of the Successor states of Uttar Pradesh and Uttaranchal;

Now therefore, in exercise of powers conferred upon it under the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Central Government, hereby makes the following order, namely: -

I. Definitions: -

- (a) 'erstwhile Corporation' means the Uttar Pradesh Forest Corporation as it existed before the Ninth day of November, 2000 and continued under sub-section (1) of section 67 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 till the First day of April, 2001;
- (b) 'successor Corporations' means in relation to the State of Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh Forest Corporation (UPFC) and in relation to the State of Uttaranchal, the Uttaranchal Forest Development Corporation (UFDC).

II. Order: -

(i) Assets:

- (a) Fixed assets (land and buildings etc) of the erstwhile Corporation situated in either Uttar Pradesh or Uttaranchal will pass on to the Successor Corporation of the State in which they are located.
- (b) Movable assets and stores of the field units shall be transferred on the basis of location. Stores, furniture and vehicles of the Head Office shall be divided according to the year of purchase in the ratio 46: 54 between the successor Corporations of Uttar Pradesh and Uttaranchal.

(ii) Liabilities:

- (a) Asset specific liability of the erstwhile Corporation shall pass on to the successor Corporation of the Successor State to which the asset has been allocated.
- (b) Liability of the erstwhile Corporation that cannot be assigned to any asset shall be apportioned between the two Forest Corporations of Uttar Pradesh and Uttaranchal in the ratio 46: 54.

(iii) Employees:

Employees of the erstwhile Corporation shall be allocated to Forest Corporation of the Successor States of Uttar Pradesh and Uttaranchal in the manner already agreed upon between the States.

(iv) Reserve and surplus:

The reserve and surplus as reflected in the balance sheet of erstwhile Corporation for the year ended 31st March 2001 will be apportioned between the successor Corporations of Uttar Pradesh and Uttaranchal in the ratio 46: 54.

[No. 13012/1/2002-S R]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.